

सवस्य

संबर्ध

44 F-0





असाधारगा EXTRAORDINARY

भाग I--सण्ड 1 PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

♥0 53 No. 531

नई बिल्ली, शनिवार, मार्च 7, 1981/फाल्गुन 16, 1902 NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 7, 1981/PHALGUNA 16, 1902

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संस्था दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रका का सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

पेट्रोलियमः रसावन ग्रीर उर्वरक मंत्रालय

(वेद्रोजियम विज्ञात)

मं करच

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1981

संक्रमा-14016/1/77-पी०सी॰III.---देश में हाल ही में प्लास्टिक की जनलब्धता महत्वपूर्ण बढ़ गई है और उत्पादन के लिए भावी योजनाओं द्वारा वेदा में प्लास्टिक रिजिस्म की काफी बड़ी मालाएं उपलब्ध कराये जाने की संभावता है। विश्व में प्लास्टिक्स का प्रयोग कड़ी लेजी से बढ बया है और मामग्री भीर कर्जा के सरंजाण में इसका विशेष महत्व है, कृषि सम्बन्धी उत्पादन बढ़ाने में इसका पर्याप्त योगदान रहा है। भारत तरकार प्यास्टिक्स के उपयोग का कृषि और सिवाई में बढ़ाते और विकसित करने के सम्बन्ध में विचार कर रही है जो कि कृषि के उत्पादन में विकास करने और कार्यकुमलता लाने के लिए एक मुख्य उपाय होगा। कृषि और इससे संबद्ध क्षेत्रों में प्लास्टिक नामग्री के उपयोग की बढ़ाने और शिकसित करने के लिए सरकार ने कृषि में प्लास्टिक्स के तपयोग पर एक राष्ट्रीय क्षमिति पठित की है जिसमें निम्नतिबित श्रिष्ठकारी कामिल होंने :---

- 1. डा॰ जी॰ बी॰ के॰ राय, ऋध्यक्ष मृतपूर्व सदस्य, योजना प्रायीग।
- 2. डा॰ एन॰ एस॰ रंघावा, जप-महासेखानिवेशक, इंडियन कार्जसिल माफ एग्रीकल्बरन रिसर्च सवस्य

- 3. श्री एस० एस० सम्बदेश, मलाहकार (पेटो-रसायन). वेदोलियम विभाग. नई विल्ली।
- 4 प्रो० ए० भी । पांड्या, निदेशक, सेंट्रल इंस्टोट्यूट भाष एग्रीकल्बरम इंजीनियरिंग, चितिरिक्त ए-इस्तक, 11 तस्र, न्ह तेग बहाद्दर कम्पलेक्स, टी० टी० नगर, बोपाल (मध्य प्रदेश)
- डा॰ ए० एम॰ माइकस, प्रोजेक्ट डाइरेक्टर, बाटर टेक्नांलोजी सेंटर. इंडियन एग्रीकरूचरक्ष रिसेंच इंस्टीट्यूट, नर्द विस्ती ।
- ६ डा० के० क्रम्याम्ति, सबस्य नंपुन्त भायुन्त, बाच विमाग. नई दिस्सी ।
- 7. श्री एमं० भाटिया, सदस्य निवेशक, (एफ० एंड एफ० पी०,) बाद्य विभाग, नई दिल्ली।

1422 GI/80

मदस्य

मदस्य श्री ए० ग्रार० एस० मुर्ति, उप-सचिवः सिंचाई विभाग, नदि विरुक्ति । नद÷य 9. श्री के० मंजया, निदेशक (सिचाई), मेंट्रल बाटर कमीशन, सई विस्ली । सदम्य 10. हा० एम० वरदाराजन, द्यध्यक्ष एवं प्रवंध सिदेशक, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० बड़ोदा स्वस्य 11. श्री एस० नारायणस्वामी, ग्राध्यक्ष, केमप्लास्ट, भद्रास । सदस्य 12. बी एम० पार्थासारथी, निवेशक, पोलियेन जनरल इंडस्ट्रीज प्रा० लि०, मद्रास सदस्य 13. श्री भाई० पी० भ्रामन्द, शिवालिक एग्रो पोली प्रोडक्टस लि०, नर्ष दिल्ली। सदस्य 14. श्री केशव प्रसाद,

समिति की मिविव श्रीमती लिलिया पी० सिंगु जो पेट्रोलियम, रसायन भीर उवेरक महालय में एक परियोजना श्रधिकारी हैं, समिति के काम में आपना सहसोग प्रदान करेंगी।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नप्रकार होंगे:---

नेशनल आर्गेनिक केमिकस्य इंडस्ट्रीज लि०,

- (1) निम्नलिखित के संदर्भ में कृषि में प्लास्टिक्स के उपयोग की संभावनाओं का पुनरीक्षण:
 - (क) पौधे स्रीर फमल का संग्धाणः;
 - (ख) सिचाई भीर जल का ईस्टब्लम उपयोग;
 - (ग) कृमिनाश्वकों भीर पौधों की पोष्टिकता का उपयोग;
 - (छ) कृषि उत्पादों का भैडारण ग्रीर ग्रनुरक्षणः
 - (इ) ग्रन्थ सम्बद्ध क्षेत्र

हैबिन इंडिया लिमिटेड,

15. श्री एम० पटवधैन,

'मद्रास ।

वस्बई ।

- (2) भारतीय परिस्थितियों के भ्रषीन विभिन्न कोंतों में प्लास्टिक्स के उपयोग की सम्पूर्ण भ्रषेक्यक्स्या का पुनरीकण भीर भारतीय परिस्थित में उपयुक्त स्थापित पर्वतियों के मनुरूप प्लास्टिक्स का उपयोग बढ़ाने के लिए उपायों का सुक्षाव देना;
- (3) तसे उत्पादों पर विस्तृत अध्ययन कानने, नये उपयोगों और कृषि के क्षेत्र में प्लास्टिक्स सामग्री का प्रयोग के लिए अपेक्षित प्रणाली पर मुझात्र देना;
- (4) क्रीय में ९४ स्थित के उपयोगों से कातावरण पर प्रमानों का गुनरीक्षण;
- (5) क्रुचि के प्रयोगों में जिसमें उद्योग के परिवर्तन के लिए प्रौदो-गिकीय समर्थेत साचीं धौर उपकरणों की उपक्रव्यता भौर ग्रामीण क्षेत्र में इन उत्पादों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए यिखमान प्रणाली की सुदृढ़ बनाने के लिए सिफारिणों करना

णामिल है, के लिए प्लास्टिक उत्पादों के उत्पादन के लिए वर्तमान मुविधाओं का पुनरीक्षण करना।

- 3. प्रारंभ में समिति की कार्य अवधि दो वर्ष के लिए होगी। समिति जितनी बार आवण्यक समझेंगी बैठके कर सकती है परन्तु एक तिमाही में कम में कम एक बार जरूर बैठक बुलायेंगी। समिति अपनी अवधि की समाप्ति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी परन्तु जब जब आवश्यक होगा, यह अन्तरिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
- 4. समिति के लिए अपेक्षित मिलवालय गम्बन्धी सहयोग पेट्रालियम विभाग द्वारा दिया जायेगा।
- 5. गैर सरकारी सद्दर्शों पर याला अले/दोन ह असे सन्बन्धों व्यथ भारत सरकार (पेट्रोलियम विभाग) द्वारा बत्न किया जायेगा। सरकारी अधिकारियों के सम्बन्ध में याला भत्ते/दैनिक भक्षे सम्बन्धों व्यथ सम्बन्धित प्रशासनिक संत्रालयों/विभागों द्वारा तदन किया जायेगा।
- 6. अगर भावस्थक होगा, सरकार सामांत के गठन में हा-फेट कर सकती है।

मह्य प्रवाद भारा, सयुक्त सन्विव

MINISTRY OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Petroleum)

RESOLUTION

New Delhi, the 7th March, 1981

No. 14016/1/77-PC.III.—The availability of plastics materials in the country has increased substantially recently and the future plans of production are likely to make available very large quantities of plastics resins in the country. The use of plastics in the world has increased rapidly and has acquired special significance in the conservation of material, energy and has contributed greatly to increase production of agriculture produce. The Government of India has been considering the promotion and development of uses of plastics in agriculture and irrigation as a major step in improving agricultural yields and efficiencies. In order to promote and develop the use of plastics materials in agriculture and associated fields, the Government has decided to constitute a National Committee on the Use of Plastics in Agriculture; the Committee will consist of:—

 Dr. G. V. K. Rao, former Member, Planning Commission.

'hairman

Dr. N. S. Randhawa,
 Dy. Director General,
 Indian Council of Agricultural Research,
 New Delhi.

Member

 Shri S. S. Sachdeva, Adviser (Petrochemicals), Department of Petroleum, New Delhi.

Member

4. Prof. A. C. Pandya,
Director, Central
Institute of Agricultural Engineering,
Addl.-A-Block, II Floor,
Guru Tegh Bahadur Complex,
T. T. Nagar, Bhopal (M.P.).

Member

Dr. A. M. Michael, Project Director, Water Technology Centre, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi.

Member

 Dr. K. Krishnamurthy, Joint Commissioner, Department of Food, New Delhi.

Member

7. Shri M. Bhatia, Director (F & FP), Department of Food, New Delhi. 8. Shri A. R. S. Murthy, Deputy Secretary

Member

Department of Irrigation, New Delhi.

Member

9. Shri K. Manjiah, Director (Irrigation), Central Water Commission,

Member

10. Dr. S. Varadarajan. Chairman and Managing Director. Indian Petrochemicals Corpn Ltd., Baroda.

Member

11. Shri S. Narayanaswamy, Chairman, Chemplast, Madras.

Member

12. Shri M. Parthasarathy, Director, Polyen General Industries Pvt. Ltd., Madras.

Member

13. Shri I. P. Anand, Shivalik Agro Poly Products Ltd., New Delhi.

14. Shri Keshav Prasad, Wavin India Limited, Madras.

Member

15. Shri M. Patwardhan, National Organic Chemicals Industries Limited, Bombay.

Member

The Comittee will be assisted by Smt. Lalitha B. Singh, Project Officer in Ministry of Petroleum, Chemicals Fertilizers, as Secretary of the Committee.

- 2. The terms of reference of the Committee would be as follows :-
 - (i) To review the possibilities of use of plastics in agriculture with special reference to-
 - (a) plant and crop protection;

- (b) irrigation and optimum use of water;
- (c) application of plant nutrients and pesticides:
- (d) handling and storage of agriculture products:
- (e) any other related area.
- (ii) To review the overall economics of application plastics in different areas under Indian conditions and to suggest measures for increased use of plastics consistent with the established practices which are suitable in the Indian context:
- (iii) Suggest in-depth studies on new products, new applications and on systems required for using plastics materials in agricultural sector
- (iv) Review the impact of the use of plastics in agriculture on environment:
- (v) Review the existing facilities for the production plastics products for use in agriculture including technological back-up for the conversion industry, availability of moulds and tools and to make recommendations on strengthening the existing system promote the production of these products in the rural sector.
- 3. The term of the Committee will be initially for a period of two years. The Committee shall meet as often as necessary but at least once a quarter. The Committee will submit its Report at the end of its term, but it should submit interim Reports as often as necessary.
- 4. The Secretarial assistance required for the Committee will be provided by the Department of Petroleum.
- The expenditure on TA/DA of the non-official Members will be met by the Government of India (Department of Petroleum). The TA/DA of the Government officials will be met by the concerned administrative Ministeries/Departments.

Government may make suitable changes in the constitu-tion of the Committee, if required.

M. P. MODI, Jt. Secy.